भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 284*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की आपूर्ति

284*. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले को उर्वरकों की किस्म-वार कुल कितनी मात्रा में कितनी आपूर्ति की जा रही है;
(ख) उर्वरकों की तस्करी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार का उर्वरक राजसहायता की राशि सीधे किसानों के खातों में अंतरित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'उर्वरकों की आपूर्ति' के संबंध में श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा पूछे गए दिनांक 08.08.2025 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 284* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): राज्य स्तर पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना उर्वरक विभाग का अधिदेश है। हालांकि, राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, चल रहे खरीफ मौसम 2025 (अर्थात 01.04.2025 से 05.08.2025 तक) के दौरान लखीमपुर खीरी जिले में उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

आंकड़े एमटी में

क्र.सं.	**उत्पाद**	**दिनांक 01/04/2025 से दिनांक 30/09/2025 तक आवश्यकता**	**दिनांक 01/04/2025 से दिनांक 05/08/2025 तक उपलब्धता**	**दिनांक 01/04/2025 से दिनांक 05/08/2025 तक डीबीटी बिक्री**	**दिनांक 05/08/2025 तक की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टॉक**
1	यूरिया	1,21,918	1,30,276	1,25,130	5,146
2	डीएपी	12,801	14,847	10,662	4,185
4	एमओपी	844	2,377	1,839	538
3	एनपीकेएस	14,329	20,032	13,178	6,854

(ख): उर्वरक को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। उर्वरकों की कालाबाजारी/विपथन/तस्करी को रोकने, और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (एफसीओ) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले ऐसे कदाचारों में शामिल किसी भी व्यक्ति/उर्वरक कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए **राज्य सरकारों को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के तहत पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं**। दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 01.08.2025 तक की अवधि के दौरान राज्यों द्वारा निष्पादित प्रवर्तन गतिविधियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों (विशेषकर नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से सटे राज्यों) से नियमित रूप से अनुरोध किया गया है कि वे भारत से पड़ोसी देशों में यूरिया की तस्करी को रोकने के लिए सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाएं।

(ग) और (घ): 'उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)' प्रणाली के तहत, प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर सब्सिडी जारी की जाती है। सभी किसानों को बिना किसी मनाही के सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 08.08.2025 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं.284* के उत्तर के भाग (ख) से संबंधित है

01.04.2025 से 01.08.2025 तक की प्रवर्तन गतिविधियों संबंधी संचयी रिपोर्ट

			कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन		
क्र.सं.	राज्य	निरीक्षणों /छापों की संख्या	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
1	आंध्र प्रदेश	577	1	1	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	1681	12	2	0	28	0	0	11	0	0	11	0	0
4	बिहार	7176	712	314	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ	3661	264	3	3	29	1	0	110	5	0	24	0	0
6	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	दिल्ली	99	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0
8	गोवा	602	544	180	6	10	0	0	32	1	0	16	0	0
9	गुजरात	4566	13	0	1	0	0	0	64	1	0	1	1	6
10	हरियाणा	4133	47	3	1	16	18	1	40	10	3	11	1	3
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	जम्मू एवं कश्मीर	1568	22	1	0	14	1	0	28	0	0	8	0	0
13	झारखंड	352	3	0	0	5	4	0	1	0	0	0	0	0
14	कर्नाटक	3538	150	10	0	117	0	0	117	10	0	56	6	3
15	केरल	323	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
16	मध्य प्रदेश	276	0	0	35	0	0	0	0	0	0	288	89	0
17	महाराष्ट्र	26870	15	0	15	0	0	0	322	35	17	1	73	1
18	मणिपुर	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19	मेघालय	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मिजोरम	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	नागालैंड	64	14	0	14	0	0	0	101	0	0	2	64	1
22	ओडिशा	3622	0	0	0	0	0	0	10	0	0	870	41	0
23	पुदुचेरी	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	पंजाब	2323	2	0	0	5	0	1	65	23	2	0	0	1
25	राजस्थान	5828	0	0	0	0	0	0	72	0	0	5	13	20
26	तमिलनाडु	10837	13	0	1	0	0	0	4	3	0	65	0	0
27	तेलंगाना	47518	0	0	1	2	0	0	6	0	0	0	0	0
28	त्रिपुरा	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	उत्तर प्रदेश	16193	999	2181	44	164	37	3	141	18	2	38	3	6
30	उत्तराखंड	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0
31	पश्चिम बंगाल	15666	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0
	कुल	**158128**	**2811**	**2695**	**140**	**391**	**62**	**5**	**1351**	**106**	**24**	**1442**	**294**	**41**